

डाक फंजीयन संख्या

एस.एस.पी.एल.डब्ल्यू/एन

पी.439/2015-2017

वर्ष : 9 अंक : 226

पृष्ठ : 8 मूल्य : 3 रुपया

लखनऊ, शनिवार, 09 दिसंबर, 2023

# द अचौकर टाइम्स



## सवाल के बदले रिश्वत के आरोप में महुआ की सांसदी गई

एजेंसी

नई दिल्ली। 15 अक्टूबर में भाजपा संसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महुआ पर कारोबारी दर्शन हीरानंदनी के कहने पर संसद में सवाल पूछने का आरोप है।

तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। ऐसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों की जांच कर रही संसद की आचार समिति की रिपोर्ट सौंपने के बाद लोकसभा में यह फैसला लिया गया है। इस रिपोर्ट में महुआ की सांसदी खत्म करने की सिफारिश की गई थी। इससे पहले

तृणमूल कांग्रेस के मुख्यमंत्री चक्रवात जगन मोहन रेण्डी ने मिचैंग के बाद की शिकायत की जायजा लेने के लिए शुक्रवार को तिरपति और बापलु जिलों का दौरा किया। आंध्र पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में चक्रवात प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लिया।

**जायजा**

इस बीच अंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चक्रवात जगन मोहन रेण्डी ने मिचैंग के बाद की शिकायत की जायजा लेने के लिए शुक्रवार को तिरपति और बापलु जिलों का दौरा किया। आंध्र पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में चक्रवात प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लिया।



### शिकायत के 54 दिन बाद गई महुआ मोइत्रा की सांसदी

मामले में निशिकांत दुबे और जय अनंत देहादराई की भूमिका क्या है? मामले में आचार समिति की रिपोर्ट क्या आई? महुआ की सदस्यता क्यों गई? अब आगे क्या होगा?

**आचार समिति में क्या हुआ?**

ऐसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले की जांच करने के बाले लोकसभा में आचार समिति ने 2 अनवरब को पूछताछ की थी। वहाँ 9 नववरब को एक बैठक में भाजपा संसद निशिकांत दुबे द्वारा शिकायत के समर्थन में बहुमत की अद्यता दिया गया। आरोप पर महुआ का क्या कहना है? इससे पहले आचार समिति के सामने खुद महुआ पर आरोप किसने लगाए हैं?

मोइत्रा को लोकसभा से निकासित

करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कांग्रेस संसद परसीत कौर सहित समिति के छह सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था। जबकि विपक्षी दलों से जुड़े समिति के चार सदस्यों ने असहमति नोट प्रस्तुत किए थे। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को %फिरस्त मैचर्स पर दिया है। इस रिपोर्ट के बाद शुक्रवार (8 दिसंबर) को महुआ की सदस्यता निरस्त करने की जिक्र करते हुए कहा था कि आरोप झूठ पर आधारित थे।

महुआ की सदस्यता गई, लेकिन आगे क्या? आचार समिति के पिछले निर्णयों से पता चलता है कि बैनल अनैतिक आचरण के दोषों पर गए सदस्य के बिलाक सदन से निलंबन, माफी या निंदा जैसे कदमों की सिफारिश करता है। हालांकि, इसके पास संसद पर मुकदमा चलाने की दावाकास्प स्मीकर से शिकायत की जांच की मांग की उहोंने दावा किया था कि ये सबूत वकील जय अनंत देहादराई द्वारा प्रदान किए गए थे। लोकसभा स्मीकर को लिखे अपने पत्र में दुबे ने कहा था कि उहें वकील और महुआ के निष्कासित कर दिया है। अब इस बात की अधिक संभावना है कि मोइत्रा इससे पहले आचार समिति के सामने खुद महुआ पर स्वीकार किया था कि

उहोंने संसद में सवाल पूछने के पोर्टर से जुड़ी अपनी आईडी-पासवर्ड साझा किए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने पहले एक बयान में अपने पूर्व साथी जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा था कि आरोप झूठ पर आधारित थे।

**संसद में रखी गई रिपोर्ट में क्या सामने आया है?**

नई दिल्ली। आचार समिति की रिपोर्ट को शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन (4 दिसंबर) कार्यसूची में शामिल किया गया था। रिपोर्ट में न सिर्फ महुआ की सदस्यता निरस्त करने की, बल्कि उनके कृत्यों को बताये गये।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए, इसकी जांच भी करने की सिफारिश के पश्च में बोट किया जायगा। इससे मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई। हालांकि, विपक्ष विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस फैसले के विरोध जताया। वहाँ लोकसभा में रिपोर्ट

पर चर्चा के बाद सदन ने समिति की सिफारिश के पश्च में बोट किया जायगा। इससे मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई। हालांकि, विपक्ष विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस फैसले के विरोध जताया।

## पैसे लेकर सवाल पूछने का पूरा मामला क्या है?



हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप झूठ पर आधारित था।

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।

हीरानंदनी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप

झूठ पर आधारित था।





# सम्पादकीय

## क्या वाकई सनातन का श्राप कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में ले दूबा है?

इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के पीछे सनातन का विरोध, सनातन के विरोध पर चुप्पी और मुस्लिम तुष्टिकरण बड़ी वजह है। एक तरफ जहां इस हार लेकर कांग्रेस में रोना-धोना मचा है, वहीं नैरेटिव का खेल भी जारी है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नवीजे घोषित हो चुके हैं। हिंदी पट्टी के तीन राज्यों- मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी हार से बौखलाई कांग्रेस और इंडिया गठबंधन फिर से एक बार क्षुद्र राजनीति पर उत्तर आया है। रस्मी तौर पर हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने अपनी हार, नाकामियों और कमियों का ठिकरा ईवीएम के सिर फोड़ा है। लेकिन इस बार विरोध सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि द्रमुक सांसद सेंचिल कुमार ने लोकसभा में बयान देकर जनादेश को 'उत्तर बनाम दक्षिण' करने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदी पट्टी के 'गौमूर' बाले राज्यों में ही चुनाव जीतती है। यह भी कोई नई बात नहीं है कि डीएमके के किसी नेता ने इस तरह का बयान कोई पहली बार दिया है, इससे पहले भी उसके नेता विभाजनकारी बयान देते रहे हैं। डीएमके सांसद का यह विवादित बयान कोई अनायास नहीं आया है, यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। द्रमुक के नेताओं ने ही 'सनातन' के समूल नाश की बात कही थी और उसकी तुलना ईड़स और कोहृ जैसी बीमारियों से की थी। बया ऐसी गालियां देना राजनीति के लिए जरूरी है? चाहे हिंदी भाषा की बात हो, सनातन संस्कृति की बात हो या फिर उत्तर-दक्षिण विवाद की बात हो, वे इसे लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। द्रमुक विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' का ही घटक-दल है। विरोध के बाद सांसद को माफी मांगने पड़ी, लेकिन ऐसा भाजपा-विरोध देश की 'विविधता में एकता' संस्कृति का अपमान और उल्लंघन है। हालांकि इस कथन को लोकसभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है, लेकिन यह अपमान कौन सहेगा?

कान लहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के पीछे सनातन का विरोध, सनातन के विरोध पर चुप्पी और मुस्लिम तुष्टिकरण बड़ी बजह है। एक तरफ जहां इस हार लेकर कांग्रेस में रोना-धोना मचा है, वहीं नैरेटिव का खेल भी जारी है। यानि कांग्रेस हार से सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी को आईना दिखाते हुए कहा कि सनातन का श्राप कांग्रेस को ले डूबा। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद लेफ्ट लिबरल मैंग और कांग्रेस समर्थक पत्रकारों-विश्लेषकों ने तरह-तरह के कुत्कर रचने शुरू कर दिए हैं। इंडिया टुडे के पत्रकार शिव अरुर ने कांग्रेस समर्थक पत्रकारों-विश्लेषकों की परतें उडाड कर रख दी है। इसी बीड़ियों को शेरर करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा, 'वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहे।' लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहे। 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती।' पीएम मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 'ऐसे लोगों की बुद्धिमत्ता है कि उन्हें आगे कई और मेल्टडाउन्स के लिए तैयार रहना होगा।' दरअसल कांग्रेस ने 70 सालों से यही अपना चाल, चेहरा और चरित्र बना लिया है। वह इस बात को समझ ही नहीं पाई सनातन संस्कृति के दम पर भारत हमेशा से धर्म परायण देश रहा है और यहां जातिवाद कभी नहीं रहा। कांग्रेस के तुष्टिकरण की पराकाष्ठा देखिए कि उदयपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने कब्रिस्तान के लिए 5 बीचा जमीन मुफ्त देने की घोषणा ही कर डाली। उदयपुर वही जिला है, जहां दर्जी कहै या लाल की निर्मम हत्या हुई और ये मामले पूरे देश में सुर्खियों में रहा था। गहलोत सरकार इस परे मामले को लेकर सवालों के घेरे में रही। सनातन के विरोध और कहै या लाल के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं करने के चलते उदयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के ताराचंद जैन ने यहां जीत का परचम लहराया। सनातन को गाली और मुस्लिम तुष्टिकरण और जिहाद को बड़ावा देना कांग्रेस को किस तरह भारी पड़ा है उसे छत्तीसगढ़ के एक उदाहरण से समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के 24 वर्षीय युवा भुवनेश्वर साहू को बेमेतरा के बिरनपुर में जिहादियों की भीड़ ने मार दिया था और उसके परिवार को कांग्रेस सरकार में न्याय नहीं मिला। उनके पिता ईश्वर साहू नितांत गरीब थे, उनको भाजपा ने 'साज' सीट से टिकट



कर्नाटक और फिर तेलंगाना की जीत इसका परिचयक है। नैरेटिव के बहाने उत्तर बनाम दक्षिण की जंग का लंबा इतिहास रहा है। कहा जाता रहा है कि विध्य के उत्तर वाले लोग विदेशी धरती से आए आर्य की संतान हैं, जबकि विध्य के दक्षिण वाले लोग बुनियादी रूप से भारत के ही लोग हैं। हालांकि दयानन्द सरस्वती जैसे लोग इसका विरोध करते रहे। आज के दौर के राजनेता सुब्रमण्यम् स्वामी हों या फिर

मानवसास्त्री, सबका मानना है कि वह हेतुर के लोग हों या दक्षिण के, वे बुनियादी रूप से एक ही हैं। शंकराचार्य ने पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में पीढ़ी स्थापित करके इस विभाजनकारी सोच पर रोक लगाने की कोशिश की थी। भारत सरकार अधिनियम के तहत जब 1937 में राज्यों में चुनाव हुए, तब से पेरियार की अगुआई में शुरू हुआ हिंदौ विरोध भी उत्तर बनाम दक्षिण की ही जंग का

विस्तार था। जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राष्ट्रपति नहीं बन पाए, तब भी उत्तर बनाम दक्षिण की वैचरिक जंग को हवा दी गई। संविधान संभा की मंजूरी के बावजूद हिंदी अगर देश की व्यावहारिक रूप से राजभाषा नहीं बन पाई, तो इसके पीछे भी उत्तर बनाम दक्षिण वाली सोच ही थी। उत्तर के राज्यों की गरीबी व पलायन और दक्षिण के अर्थिक उत्थान के पैमाने पर भी यह जंग

चलती रही है। वैसे भी देश को बांटने और किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को हँसी का पात्र बनाने की परंपरा लंबे समय से है। पर सोच के स्तर पर उत्तर और दक्षिण के राज्यों को बांटने की मौजूदा कोशिश बाकी कोशिशों से अलग है। स्वाधीनता आंदोलन की कोख से निकली कांग्रेस ने अंदरूनी राजनीति के चलते भले ही कभी ऐसी राजनीति को हवा दी हो, पर उसने खुलकर कभी ऐसी विभाजनकारी सोच को हवा नहीं दी। कांग्रेस की संस्कृति और राजनीतिक परंपरा भारत को जोड़ने की रही है, तोड़ने की नहीं। ताजिंदारी कांग्रेसवाद के विरोधी रहे समाजवादी नेता मधु लिम्बे ने अपने आखिरी लेख में कांग्रेस को देश की एकता का प्रतीक बताया था। पर लगता है कि कांग्रेस के आज के कर्णधार और उनके सलाहकारों को कांग्रेस की इस प्रकृति की जानकारी नहीं है। एक बारगी मान भी लें कि कांग्रेस का नैरेटिव सही है, कि दक्षिण के लोग उत्तर के लोगों के मुकाबले राजनीतिक रूप से परिपक्ष हैं, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि आपातकाल सही था, क्योंकि उसके बाद हुए आम चुनावों में कांग्रेस को जो 154 लोकसभा सीटें मिली थीं, उनमें से 89 सीटें दक्षिण भारत में ही मिली थीं। उत्तर में सिर्फ मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर उसे जीत मिली थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। तो फिर वह उत्तर बनाम दक्षिण को लेकर ऐसा नैरेटिव क्यों फैला रही है? तमिलनाडु में कांग्रेस 1971 के विधानसभा चुनावों से ही गायब है। अगर वह कभी दिखती है, तो द्रुतक या अत्राद्रुतक के सहरों। केरल और आंध्र प्रदेश की सत्ता से भी कांग्रेस दो चुनावों से दूर है, तो क्या यह मान लिया जाए कि इन प्रदेशों के लोगों की सोच छोटी है। आज के दौर में हर राजनीतिक दल राजनीतिक फायदे के लिए नैरेटिव गढ़ सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे देखना होगा कि उससे देश का मानस न बटे। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह विभाजन की सोच पर लगाम लगाए, क्योंकि इसका खामियाजा समूचे देश को भगतना पड़ेगा। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कांग्रेस को इससे परहेज करना चाहिए।

## विकास विरोधी नहीं हैं सुरंगें, सड़कों से बेहतर हैं अंदर के रास्ते

उत्तराखण्ड को आपदाओं के लिए नुख़्यात बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि सुरों मनुष्य के लिए न कबल महत्वपूर्ण रही हैं, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी सड़कों से बहतर हैं। पर्यावरणविदों को उम्मलय को समझना है, तो उन्हें भपने खेमों की फिक्र छोड़ जमीन और उत्तरा होगा। उत्तराखण्ड आपदाओं और हादसों के लिए



विश्वलषण म पड़ बगर आध-अधूर  
विचारों को थोप देने की प्रवृत्ति  
दिखती है। सुरंगों को लेकर अपना  
ही इतिहास खंगाल लें, तो शायद  
अनावश्यक बालने की जरूरत नहीं  
रहेगी। आदम जाति का इतिहास इस  
बात का साक्षी है कि गुफाएं हमारे  
लिए पहले चरण के आवास बने थे  
और अगर गुफा आर-पार हो गई,  
तो सुरंग का ही रूप ले लेती थी।  
अगर हम अपनी पुरानी सभ्यता में  
चले जाएं, तो राजाओं के जमाने से  
ही सुरंगों का बहुत बड़ा महत्व था।  
अपने ही देश में नहीं, बल्कि पूरी  
दुनिया में सुरंगें युद्ध से लेकर सुरक्षा  
तक में काम आती थीं। अब हमास  
और इस्लाइल के युद्ध को ही देख  
लें, किस तरह से हमास ने सुरंगों में  
एक बड़ा राज खड़ा किया है। असल  
में 18वीं शताब्दी से ही दुनिया में  
यातायात के लिए सुरंगों को बड़ा  
रास्ता बनाया गया। खासतौर से

स्कान्डनोविया या पांश्चात्या देश में सुरंगों से ही सड़कों का जाल बिछा। वहाँ सुरंगों को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और यह सच भी है। अपने ही देश में देख लें। देहारदून-दिल्ली के मार्ग में स्थित डाट काली मंदिर में बनी सुरंग अंग्रेजों की देन है। इसका सही से अता-पता हो या न हो, लेकिन यह 1800-1900 के आसपास में बनी है, जो आज तक पूरी तरह सुरक्षित है और उसके साथ ही उसी पहाड़ में दो और सुरंगें बनाई गईं, जो ट्रैफिक से निजात पाने के लिए जरूरी थीं। कच्चे-पक्के पहाड़ों में सुरंगों से नुकसानों की चर्चा में यह भी संज्ञान में ले लेना चाहिए कि डाट काली बाली सुरंग शिवालिक पर्वत श्रेणी में बनी है, जो हिमालय का सबसे नया पहाड़ है। मतलब इन सुरंगों में बेहतर दर्जे के निर्माण कार्य हुए हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखण्ड में ही

रुद्रप्रयाग के पास कदारनथ जान वाली सुरंग सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी पारिस्थितिकी सिलक्यारा जैसी है। असल में पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो सड़कों की तुलना में सुरंग इसलिए बेहतर हैं, क्योंकि एक किलोमीटर की सुरंग कई किलोमीटर के जंगल और सड़क के नुकसान से पारिस्थितिकी को बचाती है। फिर सुरंग में ऊपर के बन सुरक्षित भी रहते हैं और उन पर ज्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। दुर्भाग्य यह है कि विशेषज्ञ व पर्यावरणविद् सुरक्षित शहरी स्थानों व खुद के लिए तमाम सुविधाओं से लैस रहकर जब प्रकृति को बचाने की बात करते हैं, तो फिर बात खपती नहीं है। सिलक्यारा की घटना निर्माण प्रक्रिया में निहित दोषों का परिणाम है। सुरंग में आगे बढ़ते हुए पीछे का हिस्सा सुरक्षित करते चलना चाहिए था, जिसमें बड़ी चूक हुई। साथ ही, इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सुरंगों में समानांतर सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो निर्माण करने वाली कंपनी की जवाबदेही का हिस्सा होना ही चाहिए। इन मूदों पर बात न कर, हम उस पहलू को नहीं छूते, जो घटना से लिया हुआ सबक होता। सिलक्यारा की सुरंग के बारे में विशेषज्ञों के दल ने बड़ा खुलासा

काया तो यह एक जलागम क्षेत्र था। अब विशेषज्ञों को शायद यह पता नहीं है कि पूरा पहाड़ ही अपने आप में एक जलागम क्षेत्र है, जो वर्षा के पानी को दिशा देते हुए नदियों तक ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ, विशेषज्ञ इस बात से भी चूक गए कि सिलवर्यारा सुरांग के ऊपर जो भी बन हैं, वे चीड़ के जंगल हैं और इन जंगलों की भारी कमी यही मानी जाती है कि वे वर्षा के पानी को नहीं सोखते, इसीलिए चीड़ को विरोध झेलना पड़ता है। गौरतलब है कि जहां-जहां बन होते हैं, वहां इनकी जड़ें चट्टानों को भेदकर अपने लिए मिट्टी बनाती हैं। वनों के नीचे उनकी जड़ें चट्टानों को मिट्टी में परिवर्तित कर देती हैं, इसीलिए वे बन टिके रहते हैं। सिलवर्यारा में भी बन चट्टानों को भेदकर मिट्टी बना चुके थे और ये मिट्टी सुरंग के अंदर छत में पक्का काम न होने के कारण गिर पड़ी। असल में सुरंग में ज्यादा महत्वपूर्ण निर्माण-शैली व तकनीक होती है, क्योंकि सुरंग के भीतर चट्टानों जैसी मजबूती दी जाती है, ताकि सुरंग पूरी तरह सुरक्षित रहे। हिमालय क्षेत्र में विशेषज्ञ भरे-पड़े हैं, फिर भी यह सबसे ज्यादा आपदा झेल रहा है और उसका कारण शायद यही है कि हम भ्रमित रहते हैं। हम ऐसी घटनाओं में एक ही पहलू को बार-बार दाहरा कर अपना विशेषज्ञता या पर्यावरण के प्रति चिंता को झलकाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के विशेषज्ञों व पर्यावरणविदों को सब कुछ त्याग कर पहाड़ व बनों में रहकर आदोलनों को धार देनी चाहिए। क्योंकि ठाट-बाट, सुविधाओं, मोबाइल, मोटरों के बीच आंदोलन न तो पनपते हैं और न ही जमीनी होते हैं। बेहतर समझ के लिए उन वर्चितों के बराबर में खड़ा होना होगा, जो तथाकथित विकास में अपना हिस्सा चाहते हैं। हम उन पश्चिमी पर्यावरणविदों की तरह न बनें, जो अपने विकास के लिए दूसरों के हिस्से के विकास की बलि चढ़ाने की जिद में हैं। विकसित देशों के पर्यावरणविदों की यही शैली है कि वे अपने हिस्से के सुख को भोगने के बाद विकासशील देशों को पर्यावरण की शिक्षा देते हैं और यह भी कहते पाए जाते हैं कि हमने गलती की है, लेकिन आप इसे न दोहराएं। इसलिए अब ज्यादा सवाल इन्हीं बातों को लेकर होने चाहिए कि हम किस तरह से विकास व पारिस्थितिकी में समन्वय रखें। हिमालय में एकमत की कमी है। हम दो खानों में बटे हैं। एक वर्ग विरोध में है और दूसरा पक्ष में है। दुर्भाग्य है कि हम विकल्प की तरफ जाने से कठरते हैं, क्योंकि हमें अपने खेमों को जिंदा जो रखना है।

# भारत ने चुना सही दास्ता



अमेरिका की एक अदालत में एक भारतीय व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें अमेरिका ने यह आरोप लगाया है कि वह गुरुपतवंत सिंह पन्न के सार्वजनिक आग्रह के कारण एक अज्ञात भारतीय अधिकारी के कहने पर उसके नागरिक की हत्या की साजिश रचा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमिटी गठित की है। अमेरिका की एक अदालत में वहां अधिकारियों ने यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है कि एक भारतीय व्यक्ति ने किसी अज्ञात भारतीय अधिकारी के कहने पर उसके नागरिक की हत्या की साजिश रची। वाइट हाउस का कहना है कि इस मामले को शीर्ष स्तर पर भारत के सामने उठाया गया है। हालांकि भारत ने अमेरिका के ऐसे किसी सार्वजनिक आग्रह के काफी पहले ही इसकी जांच के लिए हाई लेवल कमिटी गठित कर दी थी। इस नागरिक को पेरिश करने के पीछे

मानता है। हाल के वर्षों में चीन के उभार को रोकने के लिए दोनों देश और करीब आए हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र है तो भारत सबसे बड़ा। अगर कोई शाखा खालिस्तान का समर्थन करता है तो वह भारतीय लोकतंत्र के बलाफ है। दूसरी बात यह है कि उसे देशों के नागरिकों की हत्या होती। तख्तापलट, इस मामले में अमेरिका का अपना रेकॉर्ड अच्छा नहीं है। उसने खालिस्तानी निज्जर मामले में जिस तरह से कनाडा ने तरफदारी की थी, वह भी नासिब नहीं थी। खासतौर पर यह खेते हुए कि भारत विरोधी तत्वों ने वहां संरक्षण मिल रहा था। खैर, अमेरिका और भारत ताजा मामले में जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, वह रिपक्ता का सबूत है। वहीं, भारत इस मामले की जांच शुरू कर चक्का कदम उठाया है। बेहतर होगा कि यह जांच जल्द पूरी की जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सवाल यह भी उठता कि कहीं यह सब भारत और अमेरिका के संबंधों में दरार डालने की साजिश तो नहीं है। उम्मीद है कि जांच से इस मामले के सारे पहलू गमने आएंगे और किसी भी लतफहमी की गंजाइश नहीं बचेगी।

2023 के नतीजों ने भाजपा के लिए आसान की 2024 की राह

गात रविवार को चार राज्यों के विधानसभा चङाब के जो परिणाम

जीतना और आसान होगा। इसका एक सतलब यह भी निकाला जा चुनावों में महिलाएं एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरे। मध्य प्रदेश में भाजपा

एक मतलब यह भा निकाला जा सकता है कि जहां-जहां कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर होती है, संगठन और चुनावी मशीनरी के मामले में काफी कमज़ोर होने के कारण कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ जाती है और जहां कांग्रेस का मुकाबला क्षेत्रीय पार्टियों से होता है, वहां उसे सफलता मिलती है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। इन सभी राज्यों में भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था और मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। बेशक इन चुनावों में भाजपा की जीत के पीछे और भी कई मुद्दे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। जाहिर है, मतदाता उन पर भरोसा करते हैं। बूथ स्तर तक भाजपा का संगठन मजबूत है और पार्टी की चुनावी मशीनरी हमेशा सक्रिय रहती है। लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी और भी मजबूती के साथ पार्टी का चेहरा बनकर उभेरें। कांग्रेस ने बेशक राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता गंवा दी है, फिर भी इन राज्यों में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है। तेलंगाना में उसने जीत हासिल की है। राजस्थान में, जहां हरेक पांच साल सरकार बदले जाने का रिवाज है, लग रहा था कि कांग्रेस बीस-पच्चीस सीटों से ज्यादा जीत नहीं पाएगी, लेकिन अशोक गहलोत 69 सीटें पाने में कामयाब रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रदर्शन में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन उसकी रफतार बहुत धीमी है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों जगह कांग्रेस का सॉप्ट विंट कार्ड नहीं चला। इन बनकर उभरा मध्य प्रदेश में भाजपा की लाडली बहना योजना का शिवराज सिंह चौहान को बहुत फायदा मिला। इसका यह भी मतलब है कि मोदी की भाजपा को टक्कर देना या 'इंडिया' गठबंधन के इतने दलों के बीच उसकी बराबरी करने में भी अभी कांग्रेस को काफी मुश्किल होंगी। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव जीत जाती, तो 'इंडिया' गठबंधन में सीटों के बंटवारे में मुश्किल होती है। पर अब गठबंधन के दलों को कांग्रेस से सौदेबाजी करने में आसानी होगी। भाजपा के खिलाफ विषयक की ओर से एक उम्मीदवार खड़ा करने की नीति को लोकसभा चुनाव में अगर प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया, तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। 'इंडिया' गठबंधन में मोदी जैसे लोकप्रिय चेहरे के मुकाबले में कोई एक चेहरा नहीं है। इसके अलावा, गठबंधन के दलों का संगठन भी कमज़ोर है। बहरहाल, 'इंडिया' गठबंधन को अब लोकसभा चुनाव के महेनजर गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई मुश्किल होगी। इन नीतियों को देखकर निर्णायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे ही होंगे, लेकिन इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ना लजिज्मी है। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा इन राज्यों में नए चेहरों को नेतृत्व सौंपती है या पुराने चेहरे को ही नेतृत्व सौंपती है। क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाएगा? वैसे भी लोकसभा चुनाव में अब बहुत दिन नहीं रह गए हैं, इसलिए चेहरे बदलने के भी अपने जोखिम हैं। लेकिन पार्टी यह जोखिम उठा सकती है, क्योंकि उसके पास मोदी जैसा लोकप्रिय चेहरा है।







